THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) The Department of Animal Husbandry & Dairying in the Ministry of Agriculture has a Fisheries Division to look into the overall development of fisheries & aquaculture in the country including problems of fishermen. However, since fisheries is a state subject, the states have equal responsibilities in attending to the problems of fishermen in their respective states.

(b) The National Welfare of Fishermen Scheme has a component for development of model fishermen village which provides for construction of houses, tube wells and community hall for fishermen. The scheme is applicable for coastal and inland States and the Union Territories.

(c) and (d) Yes sir, The technical staff of the Fisheries Department of the Government of Andhra Pradesh at district level are preparing schemes and rendering necessary assistance to fishermen's co-operatives for economic development. The National Co-operative Development Corporation also has technical experts to advise the fishermen's co-operatives to draw up plans for their economic development.

प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना

1698. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने हेतु कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) जी, हां।

(ख) प्राकृतिक आपदा प्रबन्ध कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप किए जाते हैं ताकि प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके। इन कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) प्रत्येक वर्ष अक्तूबर के दूसरे बुधवार को मनाए जाने वाले "विश्व आपदा न्यूनीकरण दिवस" के अवसर पर प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में परिशिष्ट के रूप में विज्ञापन जारी करना;

(ii) विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के आने पर "क्या करें", क्या न करें" बताने वाले पर्चों का वितरण;

(iii) स्कूली बच्चों में "लर्निंग अबाउट नैचुरल डिजास्टर्स, गेम्स एण्ड प्रोजेक्ट्स फॉर यू एंड यौर फ्रैन्ड्स" नामक पत्रिका का वितरण;

(iv) जन जागरण हेतु स्लोगन युक्त डाक लेखन सामग्री का प्रयोग; तथा

(v) दूरदर्शन और रेडियो पर सामूहिक विचार-विमर्श।

प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए राज्य सरकारें भी स्वयं उपयुक्त कार्यकलाप करती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

फलों का समेकित विकास किया जाना

1699. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में फलों के समेकित विकास संबंधी कार्य में बड़ी और छोटी पौधशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने भविष्य में लक्ष्य-प्राप्ति हेतु क्या प्रयास किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 54 बड़ी तथा 421 छोटी नर्सरियां स्थापित की गईं जबकि लक्ष्य क्रमशः 85 बड़ी तथा 350 छोटी नर्सरियों की स्थापना का था। बड़ी नर्सरियों के लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी का मुख्य कारण सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य सरकार के जरिये इसकी स्थापना में अधिक लागत का होना था।